कोटे समाप्त किए जाने चाहिए। सभी मंत्रालयों/विभागो को 18.7.1996 को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है, उपलब्ध सूचना के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त सरकारी निर्णय के बारे में कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया है। तथापि, विवेकाधीन कोटों से संबंधित कतिपय मामले उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयाधीन है।

(ग) और (घ) सरकार को सांसदों द्वारा उपयोग की गई सभी विवेकाधीन शक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी विशिष्ट निर्देश की जानकारी नहीं है। सरकार ने सांसदों से संबंधित सभी विवेकाधीन कोटों को समाप्त करने के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया है।

हरियाणा में अंगूर प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

3924. **श्री रामजीलाल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान हरियाणा में अंगूर के प्रसंस्करण हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अनुरोधों पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) पिछले पांच सालों के दौरान हरियाणा में अंगूर के प्रसंस्करण हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Reboring of tubewells for water to Srinivaspuri

3925. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 340 given in the Rajya Sabha on the 25th August, 1995 and state:

(a) whether two tubewells in Srinivaspuri are yet to be installed; if so, the reasons therefore;

(b) the action taken against the officials, responsible for the delay;

(c) whether the per capita availability of water there is inadequate to maintain basic hygiene standards; and

(d) if so, by when the said tubewells are likely to be rebored?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The reboring of two tubewells in Sriniwaspuri has already been completed and tubewells have been commissioned.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Do not arise in view of reply given to part (a) above.

Village information centres

3926. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report, captioned; "Info highway to create 35.5m rural jobs", appearing in the Tribune dated August 7, 1996, regarding exploitation of Internet's potential to provide employment to millions of jobless by setting up very small information villages, on the pattern of one being set up in Kottayam, Kerala; and

(b) if so, the steps, if any, contemplated to exploit such employment potential for the rural unemployed youths in the area of information technology, by setting up such village information centres, as contemplated in the said scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) Yes, Sir. The *report captioned "Info Highway to create* 35.5 million rural jobs" in the Tribune